एकता परिषद

राहत अभियान

14 – 20 मई 2020 संस्करण क्रमांक – 11

पलायन से वापिस लौटे मजदूरों के लिए एकता परिषद एकजुटता एवम् हिम्मत संवर्धन अभियान

20मई 2020 तक का सेवा कार्य

मास्क भेंट सुरक्षा वंदन
55500

सूखा राशन एक सप्ताह के लिए
10150

सूखा राशन दो सप्ताह के लिए
12275

बच्चों के लिए पूरक आहार
2000

कोरोना एकता केंटीन भोजन
850

जन सेवा के लिए समर्पित कहीं भी कभी भी

"अविश्वास और अनिश्चितता से घिरे मजदूरों ने किया घर के लिए रुख"

हेल्पलाइन ने जोड़ा एकता परिषद से, संगठन ने दिया घर तक साथ

कुलदीप तिवारी, ग्वालियर

गरीब और संसाधन विहीन परिवारों के युवक जवानी की सीढ़ी पर पैर रखते हि उन्हे काम धंधे की फिक्र सताने लगती है। मां बाप इतने समृद्ध नहीं है कि जवान हुए बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सकें। युवाओं में भविष्य की चिंता रहती है कि कमाएंगे तो परिवार बसेगा अन्यथा ऐसे ही जीवन बिताना पड़ेगा। बस इसी हड़बड़ी में मध्यप्रदेश के लाखों नौजवान दूर दूर तक काम करने के लिए निकल जाते हैं और साधारण समय में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति काम से मिलने वाली मजदूरी से वह कर भी लेते हैं।

ऐसे ही नवजवानों का एक 34 सदस्यीय दल मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले मंडला से निकल कर दक्षिण भारत के चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए गया था। होली के त्योहार के तुरंत बाद ये लोग फैक्ट्री में काम करने पहुंचे थे, मुश्किल से 3 सप्ताह काम किया होगा कि पूरे देश में लॉकडाउन घोषित हो गया। प्रथम 21 दिन के लॉकडाउन से ज्यादा चिंताएं नहीं थीं लेकिन दूसरे चरण के लॉकडाउन ने इन युवकों के धैर्य को तोड़ दिया ।

ये मजदूर जिस फैक्ट्री में काम कर रहे थे वह फैक्ट्री बंद हो गई और जो कमाया था वह धीरे धीरे खत्म हो रहा था क्योंकि उसी पैसे से खरीद कर पिछले 21 दिन से भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। इन युवकों को लगा कि यदि जल्दी यहां से नहीं निकले तो भूखों मरने की स्थिति आ जाएगी लेकिन फिर भी जो पैसा इनके पास उपलब्ध था वह बहुत सीमित था। इसलिए इन्होंने हेल्पलाइन पर मदद करने वालों के लिए खोज की और वहां **एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक श्री रमेश शर्मा का फोन नंबर मिला**, फोन पर जब उन्होंने बात करके अपनी परिस्थिति के बारे में बताया तो रमेश शर्मा ने उनको ठीक ढंग से समझाया तथा सरकार से अनुमति के लिए आवेदन देने की समझाइश दी।

चुकि इनकी फैक्ट्री चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर थी यह सभी 34 युवक बिना इंतजार किए हुए वहां से चेन्नई की ओर निकल पड़े। 60 किलोमीटर दूर चल कर चेन्नई पहुंचे फिर इन्होंने श्री रमेश शर्मा जी को फोन कर बताया कि वह लोग चेन्नई पहुंच गए हैं सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है हमारे पास कोई विकल्प नहीं है,इसलिए जैसे भी होगा आगे बढ़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किसी तरह एक हजार रुपये देकर एक ट्रक ने इन सभी 34 आदिवासी युवकों को आंध्र प्रदेश के बॉर्डर तक छोड़ दिया। अब समस्या थी कि वहां से आगे कैसे निकले ट्रक वाले 5000 रुपये मांग रहे थे जो उनके पास नहीं था, 3 दिन बाद एक आर्मी के सज्जन आए और उन्होंने फिर 1000 रुपये में ट्रक वाले को तैयार किया।

इतना पैसा जुटाना बहुत मुश्किल था ऊपर से भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा था तब इन्होंने फिर एकता परिषद के साथ संपर्क किया और एकता परिषद ने स्थानीय स्तर से इन सभी 34 युवकों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई, लेकिन मंजिल अभी भी काफी दूर थी किसी भी तरह एक ट्रक पकड़ कर यह लोग तेलंगाना के पास पहुंचे। तेलंगाना एवं महाराष्ट्र का बॉर्डर हिंसा की वजह से काफी संवेदनशील बॉर्डर है जहां से पैदल निकलने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं थी। स्थानीय लोगों से पूछ कर इन लोगों ने छोटे और जंगली मार्ग को चुना जो जंगल से होकर गुजरता है। इस बार इस दल ने पैदल-पैदल 150 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश किया। अब तो इन सभी का बहुत बुरा हाल था खाने के लिए पैसे नहीं थे भूख से बेहाल थे उस परिस्थिति में फिर इन्होंने एकता परिषद के साथ संपर्क किया और एकता परिषद ने कुछ पैसे का इंतजाम इन युवकों के लिए किया जिससे सबसे पहले इन्होंने भोजन किया और उसके बाद तेलंगाना बॉर्डर क्रॉस करके महाराष्ट्र से फिर एक ट्रक पकड़ कर मध्य प्रदेश के बॉर्डर में प्रवेश किया।

मध्यप्रदेश में प्रवेश करते ही इनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैनात बसे मिल गई खाने के पैकेट भी मिल गए जहां से इन बसों ने 37 युवकों को सिवनी तक छोड़ा। सिवनी के बाद मध्य प्रदेश सरकार की दूसरी बसे लगी थी जो इनको लेकर मंडला तक आई। मंडला में आने के बाद इन सभी 37 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ उसके बाद होम क्वारांटाइन में इन सभी को उनके घर भेज दिया गया। उसके बाद फिर इन युवकों का फोन आया और उन्होंने सूचित किया आप सभी के सहयोग से हम लोग सकुशल अपने गांव पहुंच गए लेकिन हमारे ही गांव के 50 लोग हैदराबाद में फंसे हैं कृपया उनकी भी मदद कीजिए इस प्रकार मंडला जिले के 37 आदिवासी युवक 7 दिन की कठिन यात्रा करके जो कुछ कमाया था वह पूरा खर्च करके अपने घर पहुंचे और उनके मन में इस प्रकार संतोष की भावना झलक रही थी आगे हम लोग बाहर कमाई करने नहीं जाएंगे जो भी होगा यहीं पर काम करेंगे ऐसे एक नहीं हजारों युवाओं के समूह जो काम की तलाश में अपने घर से बाहर गए थे उनकी व्यथा कथाएं हैं।

संपादकीय

प्रवासी मजदूरों की बेबसी,

दर्द और पीड़ा से कराहती मानवीयता के सामने बौनी पड़ गई सेवा और सहायता

लोक डाउन के 55 दिन बाद भी प्रवासी मजदूरों के वापसी का सिलसिला थम नहीं रहा है। 2 महीने की लंबी अवधि के बाद भी इन मजदूरों को सम्मान पूर्वक घर वापसी की योजना तथा व्यवस्था नहीं बन पाई है। घर से बाहर रोजगार के लिए निकले इन मजदूरों के अंदर अविश्वास और असुरक्षा इतनी गहरी बैठ गई है कि वह किसी प्रकार घर पहुॅचना चाहते हैं।

केंद्र तथा राज्य सरकारें इन मजदूरों को उनकी सुरक्षा, रोजगार तथा आजीविका का भरोसा दिलाने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है।

यूपी-एमपी बॉर्डर के सिकंदरा में मजदूरों से भरे वाहनों की लगी लंबी कतार।

सबसे आश्चर्य की बात यह है कि प्रवासी मजदूरों को उनके प्रवास के राज्य से घर के राज्य में जाने के लिए राज्य सरकारों के बीच आपसी कोई उच्च स्तरीय संवाद नहीं हुआ है केंद्र सरकार ने भी प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के मुद्दे पर कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की है। इसके परिणाम स्वरूप कई वर्षो से प्रवास के दौरान अलग–अलग रोजगार के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर भी अपनी बोरिया बिस्तर समेट कर घर जाने की जल्दी में हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि भारी–भरकम किराया देकर प्राइवेट वाहनों से घर लौट सके और न हिं उनके पास लंबे समय तक अपने परिवार को खिलाने के लिए भोजन की व्यवस्था है। जहां भी यह लोग रह रहे हैं वहां पूरी तरह से बाजार तथा शहर बंद है इसलिए जो भी थोड़ा बहुत पैसा इनके पास बचा था उसको गिन गिन कर दिनों के हिसाब से खर्च करने के लिए मजबूर हैं।

अभी पूरे देश में मीडिया भी सक्रिय हो गया है तथा प्रवासी मजदूरों के घर वापसी की दुर्दशाओं को अखबारों में भी काफी स्थान मिल रहा है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों के घर वापसी की बाढ़ के सामने असहाय महसूस कर रही हैं। जबकि सभी राज्य सरकारें अगर मिलकर काम करती तो सभी मजदूरों को उनके कार्यस्थल से घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सकती थी और इस महामारी के फैलने की जोखिम से देश को बचा सकती।अभी सरकार के तमाम प्रयास करने के बावजूद भी दक्षिण से आने वाले महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर भारी संख्या में वापस लौटने वाले मजदूरों का जमावड़ा है। दूसरी तरफ उत्तर भारत से वापस लौटने वाले मजदूरों का जमावड़ा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के

बॉर्डर के बीच में है। इसी प्रकार उत्तर भारत से दक्षिण की ओर लौटने वाले मजदूरों का जमावड़ा राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है।

यहां पर राज्य सरकारें केवल एक ही काम कर रही हैं कि जो मजदूर एक-एक सप्ताह पैदल चलकर इन बॉर्डर तक पहुंचे हैं उनको लाठियों के दम पर खदेड़ने का काम राज्य सरकार कर रही है। यह अलग बात है की सेवा के नाम पर भी कहीं पानी तो कई भोजन के पैकेट तथा कहीं-कहीं राज्य के अंदर बसों के द्वारा घर छुड़वाने के काम भी साथ साथ चल रहे हैं।

घर लौटते प्रवासियों की पीड़ा, दुख एवं बैबसी के सैकड़ों उदाहरण राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिलेंगे, जहां बूढ़े मां बाप को कंधों पर बिठाकर ले जाते हुए बेटे दिखाई देंगे, तो वही शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति भी सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हुए मिलेंगे। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी सड़क पर दिखाई दे रहे हैं जिनके पैरों में जूता चप्पल नहीं है, इसी के बीच कई ऐसे बच्चे साथ साथ पैदल चल रहे हैं जिनके पैदल चलते चलते पैर लहूलुहान हो रहे हैं; घर पहुंचने की जल्दी और उम्मीदों के बीच कई ऐसे अभागे मजदूर हैं जो यात्रा पूरी करने से पहले ही दम तोड़ चुके हैं; कई पैदल चलने वालों के समूह जो ट्रकों या दूसरे संसाधनों से यात्रा कर रहे हैं बीच में ही दुर्घटना के शिकार हो गए। इसलिए प्रवासी मजदूरों के घर वापसी यात्रा देश की तमाम नीतियों, कानूनों तथा व्यवस्थाओं पर गंभीर प्रश्नचिन्ह छोड़ रहे हैं। जिन पर आगे चिंतन मंथन होता रहेगा।

घर में पिछले 55 दिन से बंद लोगों के भी दिल भी सड़क पर चल रहे मजदूरों के हुजूम को देख कर द्रवित हो रहे हैं, जिनमें नवजात शिशुओं से लेकर गर्भवती महिलाएं, शारीरिक रूप से असक्षम, वृद्ध सभी शामिल हैं ।

वास्तव में 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद के 21 दिनों में अधिकांशतः खेतिहर मजदूरों, सड़क पर काम करने वाले कामगारों ने घर वापसी शुरू की थी, लेकिन प्रथम लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन 2 की घोषणा के साथ ही नियमित पलायन पर गए मजदूरों का भी धैर्य जवाब दे गया और सभी लोग हर हालत में घर वापसी की हड़बड़ी में दिखाई दिए। सरकारों की इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों को संभालने की कोई तैयारी नहीं थी इसी का परिणाम है कि केंद्र सरकार द्वारा सैकड़ों श्रमिक एक्सप्रेस चलाने, हजारों बसों के इंतजाम के बाद भी सड़कों पर पैदल चलने वालों की भीड़ कम नहीं हो रही है।

इस समय सरकार द्वारा घोषित सभी घोषणाएं मजदूरों की मजबूरी के सामने फीकी पड़ रही है, और आगे के लिए सवाल भी छोड़ रही है कि क्यों मजदूरों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया? क्यों मानवीयता संवेदनहीन हो गई? क्यों राज्यों की पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले मजदूरों को तपती धूप में रोकने के लिए मजबूर किया? क्यों राज्य सरकारें आपस में समन्वय स्थापित नहीं कर पाईं? ऐसे तमाम सवाल भविष्य के चिंतन मंथन के लिए छूट गए हैं। सरकार भी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कैसे विकास की धारा को आमजन की तरफ मोड़ती है,। इन सारे सवालों से सरकार और समाज को दो चार होना पड़ेगा ताकि भविष्य में इस प्रकार की त्रासदी से देश को बचाया जा सके।

एकता परिषद से जुड़े हजारों लोग आज भी लॉकडाउन में फंसे हैं तथा लगातार संपर्क कर रहे हैं, जबकि हजारों लोग घर पहुंच चुके है । मुरैना जिले के 42 मजदूर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से घर आने के लिए बैचेन हैं। 61 लोग केरल के पालघट में फंसे है। जो कमाया था उससे खरीद कर खाने की व्यवस्था कर रहे है। इनके पास राजधानी ट्रेन से आने का पैसा नहीं है । धार जिले की कुक्षी तहसील के 47 लोग अभी भी मुंबई में घर वापसी के इंतजार में बैठे हैं। श्योपुर जिले के 102 मजदूर युवक गुजरात के कच्छ में फंसे हैं। बिहार के गया जिले के 37 लोग पंजाब के कपूरथला में बिना काम के बैठे हैं। मध्यप्रदेश के मंडला जिले के 54 युवकों ने हैदराबाद से पैदल चलना शुरू कर दिया है तथा लगातार संपर्क कर रहे हैं । मणिपुर के 35 लोग कोलकात्ता में घर वापसी के प्रयास में हैं। इसी प्रकार बैंगलौर में मणिपुर के इंफाल के 175 लोग घर जाने की अनुमति के इंतजार में बैठे है। इस प्रकार से संगठन से जुड़े लोग लगातार सहायता के लिए संपर्क कर रहे हैं। एकता परिषद भी अपने सीमित साधनों एवम् स्थानीय लोगों की मदद से हरसंभव सहायता करने में लगी है ।

अंततः अजमेर में फसे बंधाली के मजदूरों ने 55 दिन बाद बड़े संघर्ष कर प्राप्त की मंजिल, पहुँचे घर

एकता परिषद श्योपुर की मदद से मिला दाना पानी – लखन सहरिया बन्धाली

जयसिंह जादौन,श्योपुर

जिला श्योपुर – यह दास्तान अजमेर जिले के नसीराबाद तहसील के ग्राम रामसर की है जहां श्योपुर जिले की कराहल तहसील के ग्राम बंधाली के सहरिया आदिवासियों की है जो यहां से होकर मथुरा रिफायनरी तक जा रही गैस की पाइप लाइन पर एक ठेकेदार के यहां मजदूरी करते थे परन्तु कोराना महामारी के करण लगे लॉकडाउन ने इनके जीवन को अस्तव्यस्त कर दिया। लॉकडाउन के बाद इनका ठेकेदार इन्हें बीच मंझधार मे छोडकर बिना यह सोचे कि इनका क्या होगा भाग गया। इधर लॉकडाउन के बाद प्रशासन ने इनके आने का रास्ता भी रोक दिया। अब तो इनके सामने खाने पीने का संकट पैदा हो गया इस बात की जानकारी इनमें से एक मजदूर लाखन सहरिया ने अपने साले नीरज को दी जिसने इस जानकारी को वाट्सएप पर ग्रुप कोरोना के जंग में हम सब संग मे पर मदद हेतु डाल दिया तथा उन मजदूरों मे से लाखन और राम अवतार के नंबर भी दिये इस पर महात्मा गांधी सेवा आश्रम के प्रबंधक जयसिंह जादौन ने लाखन से चर्चा की तो उसने बताया कि यह स्थान अजमेर जिले की नसीराबाद तहसील के रामसर गांव से एक किमी दूर है जहां उन्होंने अपना अस्थायी डेरा डाल रखा है तथा जिस ठेकेदार के साथ वे काम करते थे वो उन्हें बेसहारा छोडकर चला गया है उनके पास जो पैसे थे वो भी खत्म होने के कगार पर है।

इन बेसहारा लोगों की सहायता हो सके इसलिये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कर्मचारी एवं उनके पूर्व परिचित समाजसेवी विक्रमसिंह से चर्चा की जिन्होंने वहां के एस. डी. एम. ऑफिस के कंट्रोल रूम का नंबर दिया तथा डायरेक्टरी से ए. डी. एम. अरविंद सेंगवा का भी नंबर प्राप्त हुआ। कंट्रोल रूम पर बात करने पर वहां बैठे सज्जन ने बात गौर के साथ सुनी तथा कहा कि लॉकडाउन मे हम उन्हें यहां से भेज तो नहीं सकते पर उनकी यहां पूरी मदद की जायेगी। उन्होंने लाखन का नंबर भी ले लिया बाद मे लाखन ने बताया कि कंट्रोल रूम के द्वारा उनसे संपर्क किया गया है तथा उन्हें गांव के स्कूल में जाने की सलाह दी गई है पर हम यहीं अपने डेरे पर रहना चाहते हैं यह बात कंट्रोल रूम तक पहुंचाई गयी इस बात को मानते हुए रात को ही तहसीलदार को 10 किलो आटे के साथ वहां भेजा गया तथा कहा कि सुबह पूरी व्यवस्था कर दी जायेगी।

दूसरे दिन उनके कहे अनुसार सुबह उस पंचायत का सचिव 50 किलो आटा, 9 लीटर तेल व मिर्च मसाला लेकर वहां पहुंचा तथा कहा कि वे चिंता न करें लॉकडाउन तक उनकी पूरी मदद की जायेगी। प्रशासन उस ठेकेदार की भी तलाश में है जो इन्हें इस तरह लावारिस छोडकर चला गया 18 अप्रेल को को पुनः नसीराबाद अजमेर में बन्धाली के सभी लोगो को पुनः 90 किलो आटा, 9 लीटर तेल, 9 किलो दाल मसाले दे दिया गया। 3 मई के बाद जब सब जगह से लोग गॉव पहुॅचने लगे तो इन्हें भी आस लगी कि हम भी अब गॉव पहुॅच ही जायेंगे।

लेकिन कुछ दिनों के बाद जब कहि से कोई आस नही दिखी तो उनमें से आधे लोगो ने पैदल ही निकलने की ठानी ओर 11मई,2020 को सुबह ही 15 लोगों का एक दल बच्चे महिलाओं सहित निकल पड़ा और 2 दिन में लगभग 80 किलोमीटर चलकर अजमेर ओर टोक की सीमा तक ही पहुॅच पाते कि पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया और बापस जहाँ से चले वही पहुचा दिया। ओर कहा कि आपके खाने की व्यवस्था करते है आप सभी यही रुके। लेकिन रात तक कोई नही आया तब रात्रि 9 बजे उन्होने जयसिंह

जादौन को फोन किया कि हमारे साथ ये हुआ

अब खाने की कोई व्यबस्था नही है जो प्रशासन के लोग कह कर गए थे उन्होंने भी सुध नही ली। रात्रि तो बच्चों को बिस्कुट खिलाकर निकाल लेगे लेकिन सुबह क्या होगा ये चिंता है। जादौन जी द्बारा पुनः SDM नसीराबाद कंट्रोल रूम से बात की जिस पर सुबह व्यबस्था करने की बात हुई। और पुनः उन्हें याद दिलाया जिस पर प्रशासन ने तत्काल 40 किलो आटा, 4 लीटर तेल, आलू, प्याज और मसालों की व्यवस्था की गई।

पुनः इन्तजार की हद हो गई ओर सभी ने चलने का मन बनाया और पुलिस को बताया कि अब बहुत हो गया हम पुनः चल पड़ेंगे। इस पर पुलिस बालो ने हमे एक मैटाडोर से कोटा भेजने का बिष्वास दिलाया।

अंततः बन्धाली गांव के 32 लोग जो रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर में फंसे थे बे सभी 15 मई 2020 को सुबह पुलिस की मदद से मेटाडोर से बदलते – बदलते रात कोटा पहुँचे, वहाँ से 16 मई को सुबह पुलिसकर्मियों की मदद से एक ट्रक में बिठवाया ओर इटावा तक छोड़ा। वहाँ से पैदल चलते चलते रास्ते मे एक गाँव मे कुछ लोगो ने मदद की खाना खिलाया ओर टेक्टर से खतौली तक छोड़ा और वहीं पटवारी ने लिखा पढ़ी की, लिस्ट बनाई ओर म. प्र. चेक पोस्ट पर रोका। जहाँ पहले से ही SDM श्योपुर से बात करके रख्खी थी इसलिये बॉर्डर पर बस से श्योपुर लेकर आये जहाँ हॉस्पिटल में सबकी जांच करके अपने गांव बन्धाली भेज दिया गया

लाखन सहरिया बन्धाली ने कहा कि अगर एकता परिषद के लोग मदद नही करते तो भुखन मर जाते ।

कोरोना ने कम की सरकार और संस्थाओं की दूरी।

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चल रही है पहल ।

उदयभान सिंह जी,मुरैना

जिला मुरैना – यह कम ही देखने को मिलता है कि सरकार और सामाजिक क्षैत्र में काम करने वाली संस्थाये किसी एक मुद्दे पर सहमत होकर मिल कर काम करें। लेकिन आज कोरोना महामारी के कारण देश के कई हिस्सों से सरकार और संस्थाओं का एकजुट होकर काम करने की खबरे निरंतर आ रही है ।

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में भी जिला प्रशासन और क्षेत्र में दलित आदिवासियों के बीच लंबे समय से कार्य कर रहे एकता परिषद जन संगठन मुरैना द्वारा जिले के अति पिछड़े आदिवासी अंचल पहाड़गढ़ ब्लॉक में रहने बाले सहरिया आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए इस कोरोना संकट के समय मे उम्मीद के दरबाजे खोल दिए हैं ।

इस माह के प्रथम सप्ताह में जब गांधी आश्रम और एकता परिषद के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर से मिलकर उन्हें क्षेत्र की समस्याओ से अवगत कराया उससे पहले तक उन्हें यह उम्मीद नही थी कि जिला प्रशासन का सहयोग इतनी सहजता एवं इतने बड़े रूप में प्राप्त होगा। परन्तु जिले की संवेदनशील एवं अनुभवी जिला कलेक्टर महोदया श्रीमती प्रियंका दास ने समस्याओ को सुनते ही जिला प्रशासन की ओर से स्वयं क्षेत्र में साथ काम करने की सहमति दी, जिसके तहत बर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम

चरण में अदिबासी परिबारो को तत्काल राहत

आदिवासियों को वितरित की खाद्य सामग्री

जिला प्रशासन गाँधी आश्रम एकता परिषद ने बाँटा राशन

जौरा

जिला प्रशासन, महात्मा गांधी सेवा आश्रम एवं एकता परिषद के तत्वाधान में पहाडगढ क्षेत्र के आदिवासी अंचल के बघेवर एवं देवगढ गांव के लगभग 200 परिवारों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया।

गुरूवार को एसडीएम नीरज शर्मा एकता परिषद के उदयभन सिंह परिहार, महात्मा गांधी सेवा आश्रम के प्रफुल्ल श्रीवास्तव, शीतल जैन, राजेश राजावत, हरीओम आदि की मौजूदगी में पहले बघेवर गांव के 120 आदिवासी परिवारों को चावल, आटा, दाल नमक, मिर्च, तेल सहित आदि खाद्य सामग्री वितरित की गई। इस दौरान आदिवासियों ने एसडीएम नीरज शर्मा से कहा कि गर्मी के मौसम में पीने की पानी का संकट है लिहाजा पानी के लिए परेशानी हो रही है। शासन ने बोर तो करा दिया है लेकिन मोटर व पाइप लाइन नहीं डलने से पानी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही आने जाने वाला रास्ता पथरीला, उबड खाबड है मिट्टी या डाम्बरीकरण कराया जाये। एसडीएम ने शीघ्र ही दोनों समस्याओं को लेकर आला अफसरों से चर्चा की बात कही। यहां के बाद टीम ने देवगढ गांव के 40 आदिवासी परिवारों एवं 40 जरूरतमंदों, गरीबों के परिजनों को खाद्य राशन सामग्री वितरित की। खाद्य राशन सामग्री मिलने के बाद सभी ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी प्रसन्नता के भाव नजर आ रहे थे। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व पहाडगढ क्षेत्र के अन्य आदिवासी गांवों में कलेक्टर श्रीमती प्रियंकादास की मौजूदगी में भी जिला प्रशासन, एकता परिषद महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा खाद्य सामग्री वितरित की गई थी। उक्काश्य की जानकारी महात्मा गांधी सेवा आश्रम के प्रफुल्ल श्रीवास्तव द्वारा दी गई है।

जौरा : आदिवासियों को खाद्य सामग्री वितरित करते समाजसेवी

Scanned with CamScanner

पहुंचाने के उद्देश्य से खादय सामग्री वितरण कराने पर सहमति बनी। जिला प्रशासन की ओर से प्रत्येक परिवार को 5 किलो आटा, 1 किलो चावल, एवं हाथ धोने के लिए 1 साबुन और गांधी आश्रम एवं एकता परिषद की ओर से प्रत्येक परिवार को 1 किलो तुअर की दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो नमक, सब्जी बनाने में उपयोग होने बाले सभी तरह के मसाले 100 – 100 ग्राम तथा बीमारी से बचाव हेतु मास्क , इन सभी को मिलाकर संयुक्त रूप से वितरण करने की योजना तैयार की गई ।

इस अभियान की शिरुवात 6 मई को आदरणिया, कलेक्टर महोदया ने स्वयं उपिस्थत होकर पहाड़गढ़ बलॉक के दो गांव धोबनी ओर कन्हार में करीब 350 परिबारो को खाद्य सामग्री वितरण कर की, इसके बाद 14 मई को फिर एक बार पहाड़गढ़ ब्लॉक के ही बघेवर एव देवगढ़ गांव में जिला प्रशासन की ओर से जौरा एस. डी. एम. श्री नीरज शर्मा, सी. ई. ओ. पहाड़गढ़ श्री अजय वर्मा, पंचायत के सचिव, सरपंच एवं एकता परिषद के श्री उदय भान सिंह व गांधी आश्रम के श्री प्रफुल्ल श्रीबास्तव के सयुंक्त नेतृत्व में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया ।

अभी तक इस सयुक्त अभियान के तहत जिला प्रशासन ने करीब 30 क्वंटल आटा , 6 क्वंटल चावल, 600 साबुन तथा एकता परिषद एव गांधी आश्रम की ओर से करीब 6 क्वंटल दाल , 600 लीटर सरसो का तेल, 6 क्वंटल नमक , 1 क्वंटल 80 किलो मसाले एव 3600 मास्क उपलब्ध कराए गए है।

लॉकडाउन में फंसे 4000 बच्चों के लिए एकता परिषद कराएगा पूरक आहार की व्यवस्था

कुपोषण से जूझ रहे श्योपुर जिले में सुपोषण अभियान को मिलेगा सहारा

शबनम अफगानी,श्योपुर

जिला – श्योपुर। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का नाम आते ही कुपोषण से ग्रस्त हजारों सहरिया आदिवासी बच्चों की शक्ल सामने आ जाती है। पिछले 2 वर्षों में कुपोषण की स्थिति को लेकर सरकार तथा समाजसेवी संगठनों के द्वारा काफी प्रयास भी किए गए। इन संयुक्त प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा और श्योपुर जिले के बच्चे कुपोषण से सुपोषण की तरफ आने लगे, फिर भी पूरी तरह से श्योपुर जिला कुपोषण मुक्त हो गया यह नहीं कहा जा सकता।

पूरे जिले में लगभग एक लाख बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत हैं। इनमें से 40000 बच्चों का वजन औसत वजन से कम है। इसका मतलब यह हुआ कि 40 प्रतिशत बच्चे कुपोषण की श्रेणी में है। यही एक बड़ी चुनौती है कि इन बच्चों को कैसे कुपोषण की श्रेणी से निकाल कर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार सुपोषण की श्रेणी में शामिल किया जाए।

इसके लिए टुकड़ों-टुकड़ों में कई प्रयास चल रहे हैं जैसे - पोषण बाड़ी का विकास, पूरक आहार की व्यवस्थाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमताओं का विकास, तथा सुपोषण अभियान की महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मॉनिटरिंग करना आदि शामिल है।

इस अंचल में रहने वाले सहरिया आदिवासियों की मुख्य आजीविका मजदूरी पर निर्भर है। इसलिए प्रतिवर्ष चैत के महीने में जब फसल कटाई का समय होता है तब बड़ी संख्या में यहां के लोग परिवार के साथ पलायन करते हैं। इस वर्ष भी ऐसा ही हुआ 18000 से ऊपर सहरिया आदिवासी फसल कटाई के लिए पूरे परिवार के साथ पलायन कर गए, इनके साथ लगभग 5000 से अधिक बच्चे भी थे जो साथ में गए। निश्चित रूप से इस पलायन के दौरान बच्चों के खानपान तथा स्वास्थ्य पर स्वाभाविक रूप से प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस कटाई की मजदूरी के बीच में ही कोरोना महामारी के आने से पूरे देश को लॉक डाउन कर दिया उस स्थिति में यह सारे 18000 मजदूर मय 5000 बच्चों के फस गए। वहां न तो इनके पास काम करने के लिए मजदूरी थी और ना ही इनके रहने और खाने की कोई व्यवस्था थी। इन्होने जो भी 1 या 2 सप्ताह में मजदूरी से कमाया उसी में से खरीद-खरीद करके इन्होंने अपने लॉक डाउन के प्रथम चरण के 21 दिन निकाले। लेकिन जब लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हुआ तब लोगों के पास खाद्य सामग्री तथा पैसा दोनों ही समाप्त हो चुका था।

एकता परिषद के द्वारा सघन रूप से की गई जनवकालत के परिणाम स्वरूप राजस्थान से इन मजदूरों को श्योपुर लाने की प्रक्रिया शुरू हुई और अभी तक 90 प्रतिशत से अधिक पलायन पर गए मजदूर वापस आ चुके हैं लेकिन इनके साथ जो 5000 बच्चे गए थे यह बच्चे भी लॉकडाउन में 1 महीने तक फंसे रहे। इसलिए इनके स्वास्थ्य और पोषण पर गहरा असर पड़ा है।

पलायन और राशन की जंग के बीच, एक गांव ऐसा भी ...

डोंगर शर्मा,ग्वालियर

जिला ग्वालियर । ग्वालियर जिले का एक गांव है - कांसेर जो घाटीगांव तहसील के बरई ब्लाक में पड़ता है। सोन चिरैया अभ्यारण्य के अन्तर्गत आने वाले कांसेर गांव में 87 सहरिया आदिवासी परिवार वर्षो से निवासरत हैं। लगभग पांच वर्ष पूर्व तक ये सभी परिवार भूमिहीन थे और पूर्णतः मजदूरी से ही जीवनयापन करने के लिये मजबूर थे। वर्ष 2000 में इन परिवारों ने गांव की ही खाली पड़ी वनभूमि पर थोड़ी-थोड़ी खेती करना आरंभ किया जिससे इन परिवारों को खाने के लिये कुछ अन्न मिलने लगा लेकिन इससे सालभर का भरण-पोषण संभव नहीं था अतः वर्ष के बाकी समय के खर्चे के लिये ये सभी परिवार मजदूरी करते थे। वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू होने के बाद कांसेर गांव के सभी 87 परिवारों ने व्यक्तिगत वनभूमि के अधिकार के लिये अपने दावे दर्ज कर दिये। काफी संधर्ष के बाद इस गांव के 45 परिवारों को वनभूमि का अधिकार-पत्र मिला जिसमें महिलाओं के नाम से पट्टा भी शामिल है। शेष लोगों को अधिकार-पत्र देने की कार्यवाही चल रही है।

- व्यक्तिगत वन भूमि का अधिकार-पत्र मिल जाने के बाद इन सहरिया आदिवासी परिवारों ने एक पम्प की व्यवस्था की, जिससे सभी लोग अपनी-अपनी खेतों में सिंचाई करते हैं।
- भूमि के इस अहिंसात्मक संघर्ष की सफलता ने गांव के लोगों का हौसला बढ़ाया और वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन दर्ज किये गये। आवेदन पर त्वरित कार्यवाही हुई और वर्ष 2018 में ही 45 आवास मंजुर कर दिये गये। आज आवास बन कर तैयार हो गये हैं।
- गांव में पानी की कमी को पूरा करने के लिये पुराने कुंए को ठीक किया गया जिससे पीने और सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध होने लगा।

कोरोना काल .....

कोरोना वायरस के इस संक्रमण काल में जहां पुरा विश्व संकट के दौर से गुजर रहा है वहीं कांसेर गांव की स्थिति राहत दिलाने वाली है। पहली बार प्रत्यक्ष रुप से यह समझने का मौका मिला कि जल, जंगल और जमीन पर जनता के अधिकार होने से कैसे कठीन-से-कठीन परिस्थितियों में भी आराम से जीवन जीना संभव है। यह इसप्रकार समझा जा सकता है कि -

- कांसेर गांव का कोई भी व्यक्ति कहीं पलायन पर नहीं गया अतः लॉकडाउन के दौरान हुये प्रवासी मजदूरों की समस्या से बचा रहा साथ ही साथ बाहर से भी कोई गांव में नहीं लौटा जिससे संक्रमण का खतरा भी नहीं रहा।
- गांव के सभी 87 परिवार गेहुँ, चना और सरसों की खेती किये थे जिससे लगभग 850 क्विंटल फसल का उत्पादन हुआ है। ये परिवार पूरे समय अपने ही खेतों पर काम करते रहे। इन्हें कहीं मजदूरी नहीं करनी पड़ी।
- इतना ही नहीं खेतों से अनाज के साथ-साथ भूसा भी प्राप्त हुआ है जिसे ये 500 रुपये क्विंटल बेच रहे हैं।

इस प्रकार, एक ऐसा गांव जिसमें रहने वाले आदिवासी परिवार कभी हांडी पर लगे थे यानि बंधुआ मजदूरी करते थे, आज भूमि स्वामी है और कोरोना संकट से कोसो दूर रह कर अपनी जीवनयापन सम्मान के साथ कर रहे हैं।

कोरोना और जंगल में बसे गांव....

रामप्रकाश शर्मा शिवपुरी

जिला शिवपुरी। शिवपुरी जिले का एक गांव है- कोटरा-कोटरी (ब्लॉक- कोलारस) जिसमें सहरिया समाज के 32 परिवार निवास करते हैं। एकता परिषद द्वारा इस गांव में काम की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई तक इस गांव की स्थिति बहुत दयनीय थी। गांव पहुँचने के लिये लगभग 4 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ता था, सभी 32 सहरिया परिवार भूमिहीन थे। इनके जीवनयापन का एकमात्र साधन मजदूरी था। गांव में निवास करने वाले ये परिवार 30-35 बीघा सरकारी जमीन पर बरसात के पानी से थोड़ी बहुत सामुहिक खेती करते थे। इस गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित कराई नदी पानी का मुख्य

स्त्रोत था जिससे लोग पीने के लिये पानी लाते

थे। मूलभूत सुविधा के नाम पर गांव में न तो रोड़ था न बिजली, न पानी की सुविधा थी न स्कूल, न आंगनबाड़ी था न स्वास्थ्य की कोई सुविधा, न आवास था न शौचालय। कुल मिला कर गांव में निवास करने वाले समस्त परिवार अभावपूर्ण जीवन जी रहे थे, विभिन्न प्रकार की सरकारी सुविधाओं से वंचित थे और मजदूरी करके पेट भरने के लिये मजबूर थे।

वर्ष 2008 में गांव की स्थिति से अवगत होने के बाद एकता परिषद ने तय कर लिया कि इस गांव के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसके लिये प्रयास भी प्रारंभ कर दिया गया लेकिन गांव में पहुॅचने का मार्ग इतना खराब था कि प्रशासन या मीडिया के साथी वहां जाना ही नहीं चाहते थे। इस बीच संगठन के स्थानीय कार्यकर्ता निरन्तर गांव जाते थे, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिये आवेदन तैयार करते थे, प्रशासन को देते थे पर परिणाम कुछ नहीं आता था। इस दौरान एकता परिषद के साथियों ने गांव में मजबूत संगठन का निर्माण कर लिया था और संगठन द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों, युवा शिविरों, धरना-आन्दोलनों आदि में इस गांव के लोगों को शामिल करते थे जिससे लोगों में नेतृत्व का विकास हो और वे भी अपने अधिकारों के बारे में जान सकें। इस प्रक्रिया में एक फायदा यह हुआ कि गांव के लोगों को विश्वास हो गया कि एकता परिषद के सहयोग से वे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे।

काफी प्रयास के बाद गांव की स्थिति में थोड़ा-थोड़ा सुधार होने लगा और कुछ सकारात्मक परिणाम आने लगे। लोगों के मतदाता पहचान-पत्र और आधार कार्ड बनवाये गये। पहचान-पत्र मिल जाने के बाद सभी परिवारों के लिये राशन कार्ड बनवाया गया। इस प्रक्रिया में गांव के युवा साथियों ने सक्रिये रुप से भाग लिया। राशन कार्ड बन जाने के बाद लोगों को बहुत राहत मिली और खाने के लिये कुछ अन्न प्राप्त होने लगा।

मूलभूत संसाधन को प्राप्त करने के लिये दो स्तरों पर प्रयास किया गया- 1. प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद, और 2. स्वयं गांव वालों का प्रयास। प्रशासन से संवाद करके एक हैण्डपम्प को मंजुरी मिली लेकिन रास्ता खराब होने के कारण बोरिंग करने के लिये गाड़ी गांव तक नहीं पहुॅच पाया जिससे हैण्डपम्प भी नहीं लग सका। अन्ततः गांव के लोग इस निष्कर्ष पर पहुॅचे कि गांव की समस्याओं का समाधान न हो पाने का मुख्य कारण रोड़ का न होना है। चर्चा के बाद एकता परिषद के साथियों ने श्रमदान के माध्यम से पहुँच मार्ग को थोड़ा ठीक करने के लिये गांव वालों को प्रोत्साहित किया। अन्त में गांव वालों की पहल और श्रम से 4 किलोमीटर पहुँच मार्ग को आने-जाने लायक बना लिया गया। रोड़ बनते ही प्रशासनिक अधिकारी भी गांव में आने लगे और समस्या समाधान में तेजी आ गई । धीरे-धीरे गांव में शौचालय का निर्माण कराया गया, गांव में बिजली लगवाया गया, लोगों के बैंक खाते खुलवाये गये और पात्र लोगों को पेंशन दिलवाया गया। जिन महिलाओं के नाम से बैंक में खाते खोले गये उन सभी को, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सहरिया समाज के लिये चलाई जा रही विशेष योजना के तहत कुपोषण की राशि, 1000 रुपये प्रति माह मिलने लगा। इसके अलावा कोरोना संकट में केन्द्रीय सरकार द्वारा जनधन खाते में 500 रुपये प्रति माह डाले जाने के निर्णयानुसार, राशि खाते में आने लगी। इस गांव की सबसे अच्छी बात यह है कि गांव में कोई शराब नहीं पीता, इसका परिणाम यह है कि महिलाओं के प्रति शोषण भी बहुत कम है। इस गांव में पानी का भी सख्त अभाव है। वनविभाग की भूमि पर बसे होने के कारण गांव में रोजगार गारंटी योजना के तहत भी काम की शुरुआत नहीं की जा रही है। गांव के लोगों ने स्वयं ही कुॅआ निर्माण का काम प्रारंभ किया है।

पलायन, कोरोना, घर वापसी और राहत

कोटरा–कोटरी गांव के लोगों का जीवन मजदूरी पर ही निर्भर था अतः प्रत्येक वर्ष इस गांव से लोग पलायन करके दूसरे राज्य अथवा जिले में काम की तलाश में जाते रहे हैं। इस वर्ष (2020) भी कोटरा–कोटरी गांव से 23 परिवार काम की तालाश में मुरैना, ग्वालियर और कर्नाटक के विभिन्न स्थानों पर गये थे। कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन घोषित करने के बाद इन मजदूरों का काम भी बन्द कर दिया गया जिससे इनके सामने खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। इस बात की जानकारी मजदूरों ने एकता परिषद को दी। संगठन के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये इन सभी परिवारों को राहत सामग्री भेजी गई जिससे इन परिवारों को खाने की असुविधा न हो और प्रशासन पर दबाव बनाया गया कि इन मजदूरों को वापस बुलाया जाये। कुछ ही दिनों में 23 परिवार वापस गांव आ गये। पलायन से लौटे इन 23 परिवारों के अलावा जो लोग गांव में रह गये थे उनको भी लॉकडाउन के कारण मजदूरी नहीं मिली। गांव के कुछ लोग 7 महिनों तक कर्नाटक में फंसे रहे जिनके बुढ़े माता–पिता गांव में ही थे। इन बुढ़े माता–पिता के पास जब 3–4 दिन का राशन बचा तक संगठन के द्वारा इसकी जानकारी प्रशासन को दी गई। प्रशासन ने भी सक्रियता से काम करते हुये इन सभी परिवारों को राहत सामग्री के रुप में 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, तेल, नमक, जीरा और हल्दी, उपलब्ध कराया। इसके अलावा एकता परिषद द्वारा इस संकट काल में सभी परिवारों को 10 किलो आटा और 2 किलो दाल और दिया गया।

दमोह जिले से कोरोना राहत काल की 3 संक्षिप्त मार्मिक कहानियॉ.....श्रीनिर्भय भाई, कटनी

जिला दमोह – दमोह जिले के तेन्दुखेड़ा ब्लॉक के चदना पंचायत स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा राशन किट बांटी जा रही थी उस समय की तीन घटनायों जिन्होने काफी प्रभावित किया,

उनमें से एक चंदना .गांव मे एक बुजुर्ग जो अपने लाठी के सहारे चल पा रहे थे और लाटी लेकर ही आये हयु, थे उनके दोनों पैर मे काफी तकलीफ थी वे सीधे नही हो पा रहे थे। जब उनको उस .गोलाकार मे खड़ा कर जो सोसल डिस्टेंसिंग के लिये, चूना से गोला बनाया था, सेनेटाईजर से उनके हाथ सेनेटाईज कराये जा रहे थे तो बिना लाठी के खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। जब उनके हाथ मे 12 किलोग्राम वजन का खाद्यान्न किट दिया तो वे बुजुर्ग लाठी वही गिराकर राशन किट को बड़ी मुश्किल से पकड़ ही पाये की वो तो बांटने वाले का सहारा लेकर किट को जमीन मे रख दिया और दोनो हाथ से उस राशन किट को छूकर प्रणाम करते हुये .गांव के दूसरे नव जवान जो पंचायत के पास खड़े थे उनको सहारे के लिये बुलाया और उनके सहारे अपने घर तक उन नवजवानो के कंधे मे रखवा कर पहुंचा लिया। वह नवजवान ने जब बोरी खोलकर बोरी मे

लगे स्टीकर के अनुसार मिलाया तो वह नवजवान और बुजुर्ग इतनी प्रसन्न निद्रा मे थे कि उनकी खुशी को लेखनी मे बयान करना मुश्किल काम है।

ग्राम हर्रई मे चार बच्चों के माता का बचपन मे ही देहान्त हो .गया था। इनके पिता श्री राम सिंह .गोंड़ वर्ष 2000 मे मानपुरा से हर्रई अपने परिवार के साथ आये थे। परिवार मे राम सिंह .गोड़ उनकी पत्नि व चार बच्चे थे जो मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन कुछ ही वर्ष बीतने के बाद 2014 मे राम सिंह को अटैक आ जाने से देहान्त हो .गया। अब तो उनके परिवार का जीवन बड़ी मुश्किलों मे उलझ गया। स्व. राम सिंह की पत्नि शशी बाई को परिवार चलाना मुश्किल तो हो .गया परन्तु क्या करती उसका कोई सहारा भी नही था, मजदूरी कर अपने बच्चों को पालती रही। वर्ष 2017 मे शशी बाई का भी देहान्त हो. गया। अब तो बच्चो के भरोसे रह गया परिवार कोई नही रहा जिम्मेदार।

अब तो बच्चों को परिवार चलाना मुश्किल हो .गया। महेन्द्र प्रताप 14 वर्षीय, राहुल 13 वर्षीय, दुर्गेश 10 वर्षीय, शुभम 8 वर्षीय सभी नावालिक बच्चों का परिवार बिना जिम्मेदारी का कैसे चले। ऐसे मे बड़ा पुत्र महेन्द्र प्रताप 8वीं कक्षा की पढ़ाई छोड़कर परिवार चलाने का जिम्मा लिया और अपने पड़ोस मे रह रहे रिस्ते मे फूफा उनका सहयो करने लगे। महेन्द्र प्रताप तो पढ़ाई छोड़ दिया लेकिन अपने छोटे भाईयों को पढ़ाई मे मदद करता रहा। अब राहुल 9 वीं मे दुर्गेशा 7वीं मे, शुभम दूसरी कक्षा मे अध्ययन कर रहे है। परिस्थियों मे सुधार नही होने से उनके फूफा सुरेन्द्र विश्वकर्मा ने बच्चों को अपने घर पर ही रख लिया। परिवार का पालन पोषण किसी भी प्रकार से चलता रहा उसी बीच 2020 मे वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते पूरे भारत मे लॉकडाउन हो जाने से रोजमर्रा की मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे मजदूरों का दैनिक जीवन मे काफी असर पड़ा है। ऐसे मे इस महेन्द्र प्रताप के परिवार का जीवन और भी कठिनाई से जूझ रहा है। लगातार परेशानी से जूझ रहा परिवार अब जीवन भी बेकार सा .लगने .लगा है यह पीड़ा किसी को बयां नही पा रहे है। हर्रई .गांव मानव जीवन विकास समिति के कार्यालय का .गांव भी है जिसके चलते एकता परिषद के सहयोग से इस कोरोना कोविड-19 वैश्विक महामारी से प्रभावित परिवारों का आर्थिक सहायता हेतु कार्यकर्ताओं ने 14 प्रकार की खाद्यान्न सामग्री किट बांटी जा रही थी इसमे महेन्द्र प्रताप का भी परिवार शामिल था इस घड़ी मे ये परिवार राशन किट पाकर बहुत ही प्रसन्न था।

वनांचल .ग्राम फूलर मे जन्मी अंधो बाई का जन्म एक आदिवासी गरीब परिवार मे हुआ था। कहा जाता है कि बचपन से अंधी होने से इनका नाम माता पिता ने अंधो बाई रख दिया। अंधो बाई सांस्कृतिक कला मे बहुत ही रूचि रखती थी जब कही भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते वहां जाकर सीखती रहती थी कुछ दिनो बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम मे निपुण हो गई। जैसे ही विवाह योग्य होती है माता पिता ने एक .अंग से लाचार लड़के के साथ विवाह कर दिया और दोनो पति पत्नि मिलकर अपने जीवन को चला रहे है। अब उनके परिवार मे एक लड़का भी है जो नई खुशिया लेकर आया है। पति .गांव मे ही मजदूरी करता है और पत्नि सांस्कृतिक कार्यक्रमों मे भाग लेती इससे जो भी पैसा मिलता है उतने मे परिवार बड़ी मुश्किल से चलता है। ऐसे ही दौर मे वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते देश मे लॉकडाउन होने से ये परिवार का जीवन दूभर हो गया। अब तो कही से एक वक्त का भोजन भी मिल जाये तो खुशी होगी। ऐसा ही कुछ हुआ कि एकता परिषद के कार्यकर्ताओं की मुलाकात अंधो बाई के परिवार से हुई। इस महामारी से प्रभावित परिवार को एकता परिषद के सहयोग से खाद्यान्न राहत सामग्री किट जिसमे 14 प्रकार की वस्तुओं का किट पाकर परिवार बेहद खुश नजर आया।

मध्यप्रदेश से कोरोना काल में की गई अन्य गतिविधियॉ.....

- अशोकनगर के कार्यक्षेत्र के पलायन पर गये सभी मजदूर वापस आ गये हैं। खोरीबरी, अमोदा, दमदमा, गोरा, जमाखेड़ी, हारुखेड़ी और पारकना गांव में बाहर से आये मजदूरों को 14 दिन कॉरनटाईन में रखा गया है। एकता परिषद और पंचायत सचिव मिल कर इन मजदूरों को भोजन करा रहे हैं। इसके अलावा कार्यक्षेत्र के सभी पात्र परिवारों को 10-10 किलो चावल दिलवाया गया।
- गुना जिले के कुशेपुरा, शिकारी का टपरा, मगरोड़ा, उमर्दा, छतरपुर, धनोरिया, सिलावटी, शेखपुरा और मगरोड़ा गांव में 158 लोगों को राहत सामग्री वितरित की गई।
- अशोकनगर जिले में चन्देरी और मुंगावली ब्लॉक के लगभग 5000 महिलाओं के खाते में पैसे डलवाये गये। जिन गांवों में अबतक राषि नहीं डाली गई है उनकी सूची बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में रमपुरा गांव में जिन महिलाओं का पोषण आहार की राशि नहीं नहीं आई उनकी सूची तैयार की गई। इतना ही नहीं रमपुरा गांव से मनरेगा के तहत काम करने के इच्छुक 30 महिला और पुरुषों की भी सूची बना कर रोजगार सहायक और पंचायत सचिव को लोगों के सामने बुलाकर आवेदन दिया गया। इस आवेदन पर त्वरित कार्यवाही हुई और अगले दिन से ही काम प्रारंभ कर दिया गया जिससे उक्त 30 मजदूरों को गांव में ही मजदूरी मिल गई। एकता परिषद के कार्यकर्ता चन्द्रभान और बलवन्त भाई ने लोगों को समझाया कि काम पर जाने से पहले मास्क जरुर पहने और आपस में दूरी बना कर रखें। इसी प्रक्रिया के तहत टांडा गांव में भी मनरेगा के तहत काम करने के इच्छुक लोगों की सूची बना कर संबंधित पंचायत के सचिव और सरपंच को दिया गया है।

- ग्वालियर जिले के घाटीगांव ब्लॉक में एक गांव है आरौन। इस गांव में 2 मई को एकता परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा वंचित वर्ग के लोगों को मनरेगा के तहत काम देने के लिये 45 लोगों की सूची सहित आवेदन दिया गया था। आवेदन में यह भी लिखा गया था कि 8 दिन के अन्दर काम दिया जाये। 8 दिन इन्तजार करने के बाद 12 तारीख को पंचायत सचिव को पुनः आवेदन दिया गया। इस बार सचिव ने तत्काल कार्यवाही करते हुये मनरेगा के तहत गांव में सी.सी. रोड़ तथा अहाता बनाने का काम प्रारंभ कर दिया जिसमें सभी 45 लोगों को मजदूरी मिली। लगातार दबाव से मजदूरों को काम मिला।

- जिला सतना। ऐतिहासिक प्रसिद्ध गांव भरहुत, ददरी एवं मैनहां ब्लाक उंचेहरा जिला सतना मध्य प्रदेश में विमला बृजभान सिहं (रिटायर्डँ फौजी) ने 35 बंचित परिवारों को सूखा राशन एवं नगद राशि देकर सहयोग किया। विमला सिंह जी (शिक्षिका) एकता परिषद के राष्ट्रीय सदस्य संतोष सिंह जी की छोटी बहिन हैं। एकता परिषद के जय जगत यात्रा के संबंध में सदैव विस्तृत संवाद मे भी सजगता से यात्रा के फोर पिलर से भी प्रभावित रहते हुए संवाद करते रहे हैं। सूखे राशन मे 10 किलो गेहू, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 साबुन एवं 200 रुपये नगद के रूप में सहयोग किया । बृजभान सिंह ने कहा कि बंचितों के सहयोग मे मीडिया आदि प्रचार की आवश्यकता नहीं है, हम सब का नैतिक दायित्व है इसीलिए फोटो आदि लेने से इंकार करते हुए सहयोग किया ।

कोरोना संक्रमण–काल और एकता परिषद की महिला शक्ति ....

श्रीमति प्रीति तिवारी, भोपाल

बिहार की मंजु डुंग–डुंग से हमसब भली–भांति परिचित हैं। मंजु डुंग–डुंग सन् 1993 में एकता परिषद से जुड़ीं यानि लगभग तीन दशक से संगठन में निरन्तर सक्रिये रह कर समाज की सेवा में संलग्न हैं। गांव से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक काम करने का अनुभव रखने वाली मंजु बहन अत्यंत सरल और कर्मठ कार्यकर्ता हैं।

कोरोना संक्रमण के इस दौर में उनकी भूमिका जानने से पूर्व हमें उनके जीवन और समाजसेवा के क्षेत्र में उनके प्रवेश के बारे में जान लेना चाहिये। मंजु बहन का परिवार आर्थिक रुप से सम्पन्न नही था। बड़ी कठीन परिस्थिति में ये अपनी 10वीं की पढ़ाई पुरी ही की थीं कि वर्ष 1990 में जमीन के कारण ही इनके माता–पिता की हत्या कर दी गई। चार भाई–बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण मंजु डुंग–डुंग पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। ऐसे संकट के समय में भी मंजु बहन साहस से परिवार को संभालती रहीं। कुछ समय पश्चात, 19–20 वर्ष की अवस्था में, महिला सामख्या के माध्यम से मंजु बहन एकता परिषद से जुड़ गई।संगठन से जुड़ने के बाद जल, जंगल और जमीन के मुद्दे को लेकर जब ये बिहार के गांव–गांव में जाना शुरु कीं तब उन्हें समझ में आया कि दुनिया में जितनी गरीबी, दुःख और और शोषण है उसके सामने उनकी खुद की समस्या बहुत ही कम है और उन्होने मन बना लिया कि आजीवन इन गरीबों के बीच में ही काम करती रहेंगी। संगठन के काम के दौरान वे कई प्रशिक्षण, प्रदर्शन और भ्रमण में भाग लेती रहीं और धीरे–धीरे उनका नेतृत्व विकसित होता गया। परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बड़े ही संतुलित तरीके से संभालते हुये मंजु बहन सामाजिक काम भी करती रहीं। अपने सभी छोटे भाई–बहनों को पढ़ा–लिखा कर योग्य बनाईं। इतना ही नहीं समय निकाल कर खुद भी समाज सेवा के क्षेत्र में स्नातेत्तर तक की पढ़ाई कीं और तीन अनाथ–बेसहारा लड़कियों को पढ़ा लिखा कर बड़ा की। मंजु बहन बताती हैं कि –''जब आदरणीय राजाजी जल, जंगल और जमीन से संबंधित समस्याओं की चर्चा करते थे तो मुझे लगता था कि हमारे परिवार के बारे में बता रहे हैं क्योंकि में जन्म से ही जमीन संबंधी समस्या को बहुत नजदीक से जानती हुँ।'' बचपन को याद करके मंजु बहन बताती हैं कि –''उनकी भी पैतृक भूमि बांध के पानी में डुब गया था और फिर मुआवजा के लिये क्या–क्या करना पड़ा था, ये सब मुझे अच्छी प्रकार से याद है।'' आज संगठन से जुड़ा हुआ प्रत्येक सदस्य जानता है कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रत्येक संगठनात्मक आन्दोलनों में हमेशा ही मंजु बहन की सक्रिये भागीदारी रही है।

कोरोना के इस समय में, पिछले दो महिने से मंजु बहन ने जो सोची–समझी रणनीति के तहत काम किया है उसकी सराहना करनी होगी।

- कोरोना वायरस के बारे में जानकारी मिलने और 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लागू होने के बाद लगभग 15 दिन तो वे घर में ही रह कर समाचार सुनती रहीं और कोरोना के बारे में अच्छे से समझ लीं।
- इसके बाद मंजु बहन प्रगति समाज सेवी संस्था की मदद से साबुन बांटने के क्रम में लगभग 1000 शहरी और ग्रामीण गरीब परिवारों से मिलीं और इसी दौरान उन्हें यह समझ आया कि कोरोना से समाज में लोगों को किस प्रकार से दिक्कत हो रही है। खास तौर से एकल महिला, बच्चे, ट्रांसजेण्डर, दिव्यांग और महिलाओं की समस्याओं को नजदीक से देखी।
- इन अनुभवों के आधार पर मंजु बहन ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरुक करने तथा अति जरुरतमंद परिवारों को थोड़ी–थोड़ी राहत सामग्री देने की कोशिश कीं।
- कोरोना के समय में बिहार जैसे घनी आबादी वाले राज्य में लोगों की समस्यायें इतनी बड़ी थी कि मंजु बहन के छोटे से प्रयास का कोई अधिक परिणाम नहीं निकल रहा था।

अंत में एकता परिषद और प्रगति समाज सेवी संस्था की मदद से अबतक लगभग 300 परिवारों को राहत सामग्री बांट चुकी हैं और इस काम को निरन्तर आगे बढ़ा रही हैं.....

एकता परिषद छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने कराये मनरेगा आवेदन
90 आदिवासी मजदूरों को मिला काम

निशाद भाई, तिल्दा

- मलौद जिला रायपुर मे रोजगार गारँटी के तहत तालाब गहरीकरण का कार्य चल रहा है जिसमें कोरोना लाकडाऊन मे लोगों को रोजगार मिला और शासन के नियमों का पालन करने कि सलाह दिया गया।
- मैनपाट ब्लाक के ग्राम पंचायत कोट के आश्रित गांव घुंईडांड में मनरेगा का काम प्रारम्भ हो गया है।
- ग्राम पंचायत लाखनटोला में मनरेगा के तहत गहरीकरण का कार्य जारी।
- सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक के गांव ललाती में 24 मजदूरों के लिये तथा ग्राम घुचापुर में 25 परिवारों के लिये आवेदन सरपंच को दिया गया जिसमें मनरेगा के तहत काम देने के लिये निवेदन किया गया।

छत्तीसगढ़ एकता परिषद राहत अभियान

एकता परिषद छत्तीसगढ़ के सहयोग से जरुरतमंद परिवारों के लिये निरंतर राशन वितरण एंव किट तैयार करने का कार्य चल रहा है। जागरुकत्रा के लिये कार्यकर्ता दीवार लेखन कर रहे हैं।

ओड़िसा

स्त्रोतः रोशनआरा मोहंती

- खुर्धा जिले के कुंजुरी गांव में निवासरत् वंचित समुदाय के परिवारों के लिये एकता परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत काम की मांग की थी। इस मांग को देखते हुये कुंजुरी गांव में काम की शुरुआत की गई और मजदूरों को गांव में ही काम दिया गया। अगर इसी प्रकार रोजगार गारन्टी अधिनियम को ठीक से लागू करते हुये गांव के गरीब व वंचित वर्ग के सदस्यों को गांव में अथवा गांव के आस–पास मजदूरी मिल जाती तो पलायन का संकट पैदा न होता और लाखों मजदूर अपना पेट भरने के लिये देश के कोने–कोने में न भटक रहे होते।
- पनेल चदर गॉव में मनरेगा का काम प्रारम्भ हो गया है, पिछले दिनों वहॉ की एकता परिषद जिला समन्वयका सुश्री बिबिनिका जी ने लोगों को पंचायत भवन लेजाकर आवेदन कराया था।

असम

स्त्रोतः डिम्बेश्वर नाथ और नयनतारा, असम

- जोरहट जिले के कार्यकर्ता मोहन साकिया के द्वारा दो अत्यंत गरीब महिलाओं को कपड़ा और राषन सामग्री वितरित किया गया।
- विष्णुपुर जिले के थांगा गॉव में बच्चों के अधिकार पर कार्य करने वाले साथियों के साथ राशन और ताजा सब्जियों का वितरण किया गया।
- मणिपुर, इम्फाल के पश्चिमी जिले के गॉव में 30 जरुरतमंद लोगों को राशन दिया गया।
- इम्फाल के कैगांव गॉव में मनदेगा कार्य प्रारम्भ हो गया है, वहॉ के स्थानीय मजदूर काम कर रहे हैं।

एकता परिषद

MGNREGA में काम करते वक़्त बरती जाने वाली सावधानियां

- काम करते वक़्त एक दुसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनायें रखें
- काम पर जाते समय और वापस आते समय भी एक मीटर की दूरी बनायें रखें
- चेहेरे पर मास्क या कपडा बांधें रखें
- किसी भी औजार, फावड़ा, गुदाल को छूने से पहले और बाद में हाथ ज़रूर धोएं

https://www.ektaparishadindia.org

एकता परिषद्, संसाधन केन्द्र, पुरानी छावनी थाने के पास, ए.बी. रोड पुरानी छावनी ग्वालियर, सम्पर्क - 9993592425
Contact Persons : Ran Singh Parmar 9993592425, Email: mgsa.india@gmail.com ,
www.mahatmagandhisevaashram.org, www.ektaparishad.org